



# हरियाणा संवाद

“जितना भी हो सके, खुद में और समाज में कोशिश उजाला भरने की होनी चाहिए।”

: अज्ञात

पक्षिक 16-30 अप्रैल 2022

www.haryanasamvad.gov.in अंक -40



मनोहर लाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हरियाणा: गडकरी

3



पूजा को मिला 'नारी शक्ति पुरस्कार'

7



गुरु तेग बहादुर जी की चरण रज से धन्य धमतान साहिब

8

## राष्ट्रीयता की भावना, प्रगति का उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव



विशेष प्रतिनिधि

राष्ट्रीयता की भावना किसी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रगति का आधार होती है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश प्रदेश में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में यह उत्सव पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रगति पर है।

राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक आधार पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभागों एवं क्षेत्रों से संबंधित माननीय जन आजादी से संबंधित किसी भी स्मारक, घटना, व्यक्ति या कहानी को एक नया स्वरूप देकर लोगों के बीच प्रस्तुत करें ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना में कोई कमी न आए और नई पीढ़ी को जानकारी मिल सके कि आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार देश के लिए अपनी शहादत दी थी। इतिहास जानेंगे तो आजादी की कीमत का सही आकलन हो सकेगा।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 24 अप्रैल को पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें साला महोत्सव मनाया जाना है। इस कार्य में देश की आजादी के लिए सिख समाज से जुड़ी आजादी की गाथाओं का वर्णन प्रदर्शनी के माध्यम से होगा। साथ ही हरियाणा में सिख समाज का आजादी दिलाने में क्या भूमिका रही, उसके वर्णन का प्रयास भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूका आंदोलन के अलावा बड़खालसा की महत्ता की जानकारी भी लोगों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाए। बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के चिन्ह (लोगो) को बोर्ड व निगमों की स्टेशनरी में भी छपा जाएगा, विभागीय स्टेशनरी में इस चिन्ह को छपा जा रहा है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि हमें उन सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों के साथ उस स्थान को भी इतिहास में दर्ज करना

है जो आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में स्थानीय लोगों का योगदान अति-आवश्यक है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त, 2023 तक मनाया जाएगा और इस कार्य में के तहत मनाए जाने वाले कार्यक्रम लोगों के लिए हो तथा ये कार्यक्रम उनके घर-द्वार तक पहुंचें। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम 6557 हैं जिनमें से अब तक 2555 कार्यक्रम आयोजित कर लिए गए हैं जोकि अब तक सभी राज्यों में सबसे अधिक हैं।

**अमृत महोत्सव की वेबसाइट बनेगी**

श्री अग्रवाल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने जिलों में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्य में आयोजित

करने के लिए योजनाएं बनाएं जोकि सार्थक भी हो। इन कार्य में का एक लघु लेख, वीडियो भी बना होना चाहिए ताकि इसे सांस्कृतिक मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग केन्द्र की तर्ज पर आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट तैयार कर रहा है जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ करवाया जाएगा।

**300 करोड़ की लागत से बन रहा स्मारक**

अंबाला छावनी में 22 एकड़ भूमि पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है जिसका इस वर्ष में उद्घाटन कर दिया जाएगा। ऐसे ही, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव नसीबपुर की 41 कनाल भूमि पर शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी के पलवल रेलवे स्टेशन की घटना व रोहतक दौरे की घटना के स्थानों पर भव्य कार्यक्रम होंगे।

कुई का टंडा पानी व अमरूद के पेड़ आज भी याद हैं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे अपने बचपन के स्कूल और यादें ताजा की



मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के गांव भाली आनंदपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे जहां से उन्होंने कक्षा छठी से दसवीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 1965 में लगभग 11 वर्ष की आयु में इस विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश लिया था। उन्होंने विद्यालय परिसर में 57 वर्ष पूर्व के अनुभव सांझा किए। उन्होंने कहा कि वे बनियानी गांव से 41 एकड़ पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते थे। इस विद्यालय में आसपास के कई गांव के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उन्होंने पुरानी कुई के ठंडे पानी तथा अमरूद व बेरी की भी यादें ताजा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पूर्व अपने पुराने सहपाठियों रामफल कादयान, ओमप्रकाश, वजीर इत्यादि से मुलाकात की तथा विभिन्न विषयों पर बातचीत की।

मनोहर लाल ने इस विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों के लिए 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इन विकास कार्यों में 27 लाख रुपये की राशि से स्कूल की चार दीवारी तथा 33 लाख रुपये की राशि से स्कूल के मैदान की इन्टरलॉकिंग की जाएगी। गांव के पार्क में ओपन जिम के लिए 2 लाख रुपये, भाली से गढ़ टेकना सड़क की मरम्मत के लिए 95 लाख रुपये तथा भाली एवं बनियानी गांव में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने की भी घोषणा की।

## चंडीगढ़ पर अधिकार में नहीं कोई संशय

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए लाया गया 'संकल्प प्रस्ताव' हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। तीन घंटे तक विधानसभा में चली चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के करीब 25 विधायकों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में विचार रखे। संकल्प प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बंटवारे के लिए 23 अप्रैल 1966 को बनाए गए शाह कमीशन ने तो खरड क्षेत्र के हिंदी भाषी गांव और चंडीगढ़ को हरियाणा को देने के लिए कहा था लेकिन 9 जून 1966 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसे दोनों राज्यों की राजधानी भी बनाया गया। इसके बाद अलग-अलग समझौते हुए लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ।

गौरतलब है कि एक अप्रैल 2022 को



पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके जवाब में हरियाणा विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया।

सदन ने पंजाब के प्रस्ताव पर चिंता जताई और एकमत से एलान किया कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है, और रहेगा।

गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब की आप सरकार चंडीगढ़ के मुद्दे पर अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान बांटना चाहती है ताकि उसे चुनावी वादों पर कोई टोका-टाकी न करे। यह

आम आदमी पार्टी की केवल शरारत है जिसकी वे निंदा करते हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है और रहेगा। उन्होंने कहा कि 1966 में जब हरियाणा बना। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि सतलुज के पानी के बंटवारे पर झगड़ा नहीं है। रावी और ब्यास के पानी पर झगड़ा है। वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि एसवाईएल का

पानी हरियाणा को पानी मिलना चाहिए।

**एसवाईएल का पानी निश्चित तौर पर मिलेगा**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ के बारे में हरियाणा की ओर से कोई संशय नहीं है, पंजाब की ओर से भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी निश्चित तौर पर मिलेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। जल्द सुप्रीम कोर्ट से एसवाईएल के फैसले पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर लिया जाएगा, ताकि नहर को बनाने की जिम्मेदारी केंद्र, पंजाब या अन्य किसी संस्था को मिले। उन्होंने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है।



संपादकीय

## बदलाव आ रहे हैं

विश्व में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि ज़रूरतमंद को उसका हक घर बैठे मिले। मगर हरियाणा ने यह कर दिखाया है। व्यवस्था-परिवर्तन की शुरुआत हमारे प्रदेश से हुई है, इस पर प्रत्येक हरियाणावासी को गर्व होना चाहिए।

प्रदेश में 'अन्वयोदय-परिवार उत्थान योजना' के तहत पहले चरण में दस हजार लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है और उन्हें ऋण-स्वीकृति-पत्र एक विशेष समारोह में बांट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कहावत बदल रहे हैं। अब सरकारी कुआं हर प्यासे ज़रूरतमंद के पास जा रहा है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, 'आयुष्मान भारत योजना', परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने की योजनाएं भी जनता को समर्पित कर दी गई हैं। आयुष्मान भारत जन-आरोग्य योजना की सूची में भी 1.80 लाख की वार्षिक आय वाले लगभग तीन लाख लाभार्थियों को जोड़ दिया गया है।

इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन लाभ को पीपीपी से जोड़ने से न सिर्फ पेंशन लाभार्थियों को घर बैठे मिलेगी, बल्कि अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन पाने की निर्धारित आय का होता है तो उसकी पेंशन खुद ही उसके बैंक खाते में आने लगेगी। सिरसा व कुरुक्षेत्र में ऐसे 33 हजार नए कार्ड जारी किए हैं। इस प्रणाली से सिरसा में 49 हजार नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं जबकि कुरुक्षेत्र में लगभग 81 हजार नए कार्ड बने हैं।

इसी सिलसिले में सीएम मनोहर लाल ने वर्ष 1991 से 1993 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर-2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने को मिशन 'वचनपूर्ति' का शुभारंभ किया। इससे अब इन परिवारों का तीन दशक लंबा इंतजार खत्म हो गया। इन 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागजात सौंप दिए गए। सीएम ने कहा कि इन 30 वर्षों में इन परिवारों ने अपनी जमीन पाने की उम्मीद खो ही दी थी। वर्ष 1997 में कुछ उपयुक्त संशोधन करने के बाद कुछ भूखण्ड कश्मीरी पंडितों के पक्ष में जारी किए गए थे। यह वचनपूर्ति-मिशन विपक्ष के उन दावों का जवाब है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कश्मीरी पंडित परिवारों को दी जाने वाली पांच हजार रुपए की वित्तीय सहायता रोक दी गई है।

- डॉ. चन्द्र त्रिखा

## कश्मीरी परिवारों को मिला जमीन का मालिकाना हक



मालिकाना हक के कागजात सौंप दिए। वर्ष 1997 में कुछ उपयुक्त संशोधन करने के बाद, कुछ भूखंड कश्मीरी पंडितों के पक्ष में जारी किए गए थे। लेकिन जिन परिवारों को उस समय जमीन नहीं मिली उन्हें करीब तीन दशक तक इंतजार करना पड़ा। पूरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 209 परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति की गई है।

कश्मीरी परिवारों ने लगभग 30 साल पहले खरीदी गई जमीन का हक उन्हें दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। पंडितों ने बताया कि वर्ष 1990 में उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था और 1991-92 में वे बहादुरगढ़ आए। यहां आने के बाद, जीवन फिर से शुरू करने की उम्मीद में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा, लेकिन इसका कब्जा लेने में ही लगभग तीन दशक लग गए। उन्होंने कहा कि वे अपनी भावनाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति अपनी कृतज्ञता और खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।

झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के सेक्टर -2 में कश्मीरी पंडित परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक मिशन 'वचनपूर्ति' के तहत मिल गया है। वर्ष 1991 से 1993 तक के बीच इन परिवारों ने यहां जमीन खरीदी थी लेकिन मालिकाना हक नहीं मिल पाया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विशेष प्रयासों से अब इन परिवारों का तीन दशक लंबा इंतजार खत्म हो गया। इन परिवारों की संख्या 182 है।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित किए कुछ लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने

सलाहकार संपादक :

डा. चंद्र त्रिखा

सह संपादक :

मनोज प्रभाकर

संपादकीय टीम :

संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक

संपादन सहायक :

सुरेंद्र बांसल

चित्रांकन एवं डिज़ाइन :

गुरप्रीत सिंह

डिजिटल सपोर्ट :

विकास डांगी

## कनाडा में हेल्प डेस्क स्थापित करेगी राज्य सरकार



हरियाणा सरकार द्वारा निवेश को लुभाने के लिए कनाडा में एक हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा। हेल्पडेस्क हरियाणावी एनआरआई व देश के अन्य एनआरआई उद्यमियों को राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में इण्डो-कनाडा चैम्बर आफ कामर्स (आईसीसीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस बारे में चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया मिशन-2022 के तहत देश के विभिन्न शहरों जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, अहमदाबाद का दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एग्री आधारित उत्पादों को निर्यात करने के लिए बल देना

चाहते हैं और इसी कड़ी में हैफेड के मार्फत बासमती चावल को कुछ देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कई क्षेत्रों में आगे है जैसे कि दोपहिया उत्पादन, कार उत्पादन व आटोमोबाईल उद्योग में राज्य का अग्रणी स्थान है।

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों की सहूलियत व छूट को देने हेतु विभिन्न स्थानों को ए.बी.सी.डी श्रेणी को परिभाषित किया है। उन्होंने 'डी' श्रेणी का जिक्र करते हुए कहा कि इस श्रेणी में उद्यम स्थापित करने के लिए किफायती दरों पर भूमि, बिजली में सब्सिडी और रोजगार देने पर विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिसार में एक उत्कृष्ट एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है और यहां पर एयरोनोटिक उद्योग लगाने के विभिन्न

प्रस्ताव व प्रावधान हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ड्रोन, एयरोनोटिक्स, डाटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण व कचरा निस्तारण के क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करना चाहता है। इस मौके पर उन्होंने आईसीसीसी के सदस्यों को राज्य में इन क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में अपने-अपने उद्यम व कार्यक्रम चलाने का निमंत्रण भी दिया।

आईसीसीसी के सदस्य व हिन्दुजा ग्रुप के एडवाइजर सुनील के. चड्ढा ने कहा कि हिन्दुजा ग्रुप हरियाणा में निवेश करने के लिए विचार करेगा। चड्ढा ने मुख्यमंत्री को मुंबई में आने का न्यौता दिया और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों के साथ सीधी वार्ता हेतु पेशकश भी की। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री को लंदन आने का भी निमंत्रण दिया।

## शहीदों की गौरवमयी दास्तान ए रोहनात



देश की आजादी के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम को चिरस्थायी यादगार का रूप देते हुए अंग्रेजों की बर्बरता का गवाह रहे भिवानी जिले के रोहनात गांव पर बने नाटक 'दास्तान ए रोहनात' को हरियाणा के घर-घर पहुंचाने की पहल की गई है। नाटक का मंचन सभी 22 जिलों में करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 'रोहनात फ्रीडम ट्रस्ट' के माध्यम से इस गांव को एक नया रूप दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रमों में रोहनात गांव

की कहानी को शामिल करवाने तथा गांव में एक अकादमी की स्थापना करने की घोषणा भी की है।

उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त, 2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, जब हिसार के महावीर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पधारे थे तो उस समय मुख्यमंत्री ने अंग्रेजों की बर्बरता का शिकार रहे भिवानी जिले के रोहनात गांव में रोहनात फ्रीडम ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा का परिणाम यह रहा कि रोहनात गांव के लोगों ने देश की

आजादी के 70 वर्षों तक गांव में तिरंगा न फहराने की अपनी उस कसम को तोड़ दिया और 23 मार्च, 2018 को 'शहीदी दिवस' के अवसर पर मुख्यमंत्री से रोहनात में तिरंगा फहराया था। शहीदी दिवस के ही कार्यक्रमों के तहत 26 मार्च, 2022 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के इंदिरा गांधी सभागार एक बार फिर गवाह बना जब रोहनात व उसके आसपास के 700 से अधिक लोगों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने स्वयं 'दास्तान-ए-रोहनात' नाटक को देखा और गांव के उन महान बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। नाटक देख कर मुख्यमंत्री इतने भावुक हुए की कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए पुनः मंच पर जाकर तिरंगा लहराने से अपने-आप को नहीं रोक सके।

सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल के दिशानिर्देशों के मुताबिक अब नाटक 'दास्तान ए रोहनात' को सभी 22 जिलों में दिखाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 1857 के संग्राम में हरियाणा का योगदान अविस्मरणीय रहा है। कई इतिहासकारों ने इस पर पुस्तकें भी लिखी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिन्द सेना में भी सबसे ज़्यादा सैनिक हरियाणा के थे। आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी भी अंबाला से फूटी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुरूप अम्बाला छावनी में जी.टी. रोड पर एक भव्य संग्रहालय का निर्माण करवाया जा रहा है जिसका देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 15 अगस्त, 2022 को लोकार्पण होना अपेक्षित है। देश की आजादी के बाद भी सशस्त्र सेनाओं में हरियाणा के जवानों की भागीदारी उल्लेखनीय है और आज भारतीय सेनाओं में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है।



तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा 'स्वावलम्बी युवा-आत्मानिर्भर भारत' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिसका उद्देश्य संस्थानों में स्वरोजगार के एक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 'टेक्नोप्रेन्योर' तैयार करना है।



प्राकृतिक खेती को अधिक बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल पर इच्छुक किसान अपना पंजीकरण कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार की योजनाओं पर शोध करें आईआईएम संस्थान



मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईआईएम रोहतक के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे मैनेजमेंट में लिये हुए प्रशिक्षण और हुनर का उपयोग उद्योगों के अन्य क्षेत्रों में भी करें। युवाओं को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलें इस और विशेष ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के 11वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के 300 से अधिक युवाओं को डिग्रियां वितरित की और भारतीय प्रबंधन संस्थान के गुरुग्राम विस्तार परिसर का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक एक टीम भावना से प्रबंधन प्रशिक्षण के साथ-साथ सरकार की जनहितैषी और गरीब उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी रिसर्च करें। सरकार परिवार पहचान पत्र योजना के जरिए समाज कल्याण के कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे संस्थान से हमेशा जुड़े रहे और अपनी यादें संजोये रखें। इस संस्थान में वर्ष 2012 में केवल 7 लड़कियों ने डिग्री हासिल की थी लेकिन इस साल 71 प्रतिशत लड़कियां हैं। यह रुझान सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक करता है। समारोह में अनुष्का दहिया व निगधा ओवाला को गोल्ड मैडल से नवाज गया।

# दुनिया से जोड़ने वाला सेतु है गुरुग्राम

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में किया करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण



मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा का एक महत्वपूर्ण नगर है और हम गुरुग्राम को केवल शहर के तौर पर नहीं देखते बल्कि गुरुग्राम ने विश्व भर में जो ख्याति प्राप्त की है, उससे यह शहर हरियाणा को दुनिया से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अंडरपास,

फ्लाईओवर के अलावा सिग्नेचर टावर व इफको चौक पर बने दो फुटओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। उन्होंने इसी स्थान पर गुरुग्राम के सेक्टर-111 से 115 के लिए जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का उद्घाटन भी किया। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे 92 हजार आबादी को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लागू किया लेकिन गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट सिटी बनाया जाएगा। हम सन् 2031 तक की गुरुग्राम की 42 लाख की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि लोगों को भविष्य में भी कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनसे गुरुग्राम शहर में हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन क्षेत्र जाममुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार,

गुरुग्राम को ट्रेफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से कई परियोजनाएं इसी साल पूरी हो जाएंगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक पर 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा फ्लाईओवर 30 जून तक पूरा होगा और लगभग 25.5 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे राव महावीर चौक के सुधारीकरण का कार्य भी जुलाई अंत तक पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार, लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता की ही देन है कि आज गुरुग्राम का कोई भी हिस्सा विकास से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर जाम लगा रहता था लेकिन अब परियोजनाएं पूरी होने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी और लोगों के कई घंटों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की ईमानदारी विपक्ष को खटकती है लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदारी से पूरे प्रदेश का समान विकास करवा रहे हैं।

-संवाद ब्यूरो

## मनोहर लाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हरियाणा: गडकरी

सोनीपत में 2872 करोड़ की 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन

विशेष प्रतिनिधि

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन का होना बेहद जरूरी है। जहां भी ये चारों चीजें होंगी वहीं रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योग भी वहीं लगेंगे और विकास भी वहीं होगा। खुशी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां कृषि और उद्योग में अच्छा विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इतने रोड बनेंगे कि हरियाणा सड़कों में भी नंबर वन हो जाएगा।

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हरियाणा में एक भी ब्लैक स्पॉट को नहीं रहने दिया जाएगा। सभी का सुधार होगा। हरियाणा सरकार जितने भी ब्लैक स्पॉट को चुनकर भेजेगी, जहां हादसे होते हैं, उन सभी जगहों को ठीक करेंगे। केंद्रीय मंत्री सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2872 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने 132 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जींद-गोहाणा एनएच-352ए, 183



करोड़ की लागत से बने भिवानी-मुंडाल-जींद एनएच-709ए, 136.25 करोड़ की लागत से बने झज्जर-लोहारू एनएच-334बी, 1020 करोड़ की लागत से बने यूपी/हरियाणा बॉर्डर से गोहाणा एनएच-334 बी और 1400 करोड़ की लागत से बने मुकरबा चौक से पानीपत एनएच-44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

उन्होंने 600 करोड़ की लागत से बनने वाले जींद-गोहाणा-सोनीपत-शामली रोड को

बनाए जाने को मंजूरी दी। इसके अलावा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर सिरसा के चौटाला से शामली तक के रोड अलाइनमेंट करवाने के लिए कहा। इनके साथ-साथ पंचकूला शहर में फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में रिपोर्ट मंगाने के लिए भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सड़क से जुड़ी जो भी मांग करेगी, उसे पूरा किया जाएगा। 40 साल में कोई ऐसी घोषणा नहीं जिसे पूरा न किया हो, जो बोलेंगे, वो करेंगे और जो करेंगे, वही

बोलेंगे।

दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में पहुंचेंगे

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में लगातार सड़कों का विकास हो रहा है। सड़कों की वजह से कुछ दिनों में दिल्ली से अमृतसर की दूरी महज 4 घंटे में तय की जा सकेगी। इसी तरह दिल्ली से कटरा 4 घंटे लगेगी। उन्होंने अटल टनल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले मनाली-रोहतांग के रास्ते

पर इस जगह को पार करने के लिए साढ़े तीन घंटे लगते थे लेकिन अब यह दूरी महज 9 मिनट में तय की जा सकती है। दिल्ली से हरियाणा के लोग मुंबई महज 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकेगी। सड़कों का इतना जाल बिछाया जाएगा कि यातायात बेहद सुगम हो जाएगा।

पॉड टैक्सी के लिए मांगा हरियाणा से प्रस्ताव

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में पॉड टैक्सी की शुरूआत करने की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका विभाग इस पर काम कर रहा है। दिल्ली से सोनीपत और पानीपत के लिए 250 लोगों के लिए पॉड टैक्सी की शुरूआत करेंगे, इसके लिए हरियाणा केंद्र को प्रस्ताव भेजे, जल्द काम शुरू किया जाएगा।

नितिन गडकरी ने कहा कि हमें हरियाणा को ग्रीन बनाने पर जोर देना चाहिए। ग्रीन ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। पेट्रोल-डीजल की बजाए एथनॉल व इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने पर जोर देने के लिए कहा। इससे प्रदूषण भी कम होगा और ईंधन का खर्च भी कम होगा। एथनॉल से आधे पैसे में गाड़ी चलाई जा सकती है।



राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस की मदद से मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई नई प्रणालियां शुरू की गई हैं, जिससे नागरिक-केंद्रित सेवाओं का पेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित हुआ है।



हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य के तहत सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और चार अंकों के 1064 नंबर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

# फर्क साफ है, क्यों



मनोज प्रभाकर

शासन-प्रशासन में ईमानदारी व पारदर्शिता का प्रमाण यह है कि आज किसी भी जन प्रतिनिधि अथवा अधिकारी के आगे पीछे 'पच्ची व खर्ची' वालों की भीड़ दिखाई नहीं देती। राज्य स्तरीय सचिवालय, जो आगंतुकों की आवाजाही से ठसाठस भरा रहता था, अब नहीं रहता। कार्यालय हो या फील्ड, हर जगह मंत्री-संतरी आराम से आते जाते हैं और कामकाज निपटाते हैं।

विभागीय कामकाज ऑनलाइन होने से

सरकारी कार्यालयों में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। कोई भी व्यक्ति या परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे इसके लिए राज्य सरकार अंत्योद्यम की भावना से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबका साथ और विश्वास लेकर सबका विकास कार्य कराया है। आने वाले दिनों में विकास की यह गति और तेजी पकड़ेगी। प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और एक समान हो रहा है। उल्लेखनीय यह है कि विकास के इस दौर को देखते हुए यह कतई नहीं कहा जा सकता कि विकास में किसी प्रकार का क्षेत्रवाद, भाई

भतीजावाद या कोई और अन्य वाद बरता गया है।

प्रदेश के सभी नब्बे हलकों को तवज्जो दी गई है। ऐसा नहीं है कि जहां सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक नहीं है वहां का विकास अपेक्षाकृत कुछ कम हुआ हो। ढांचागत विकास हो या सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का विषय, हर ओर

किया गया है। सिस्टम में पारदर्शिता आई है और लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस व्यवस्था परिवर्तन से हरियाणा में उद्योग-धंधे लगाने वाले निवेशकों का भी प्रदेश के सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। ईज आफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा 2014 में 14वें स्थान पर था। व्यवस्था परिवर्तन के बाद अब उत्तर भारत में नम्बर वन है, तथा पूरे देश में तीसरे



ध्यान दिया गया है। सभी विधायकों को विकास कार्यों के लिए एक समान पांच-पांच करोड़ रुपये की राशि दी गई है। विकास के पूरे परिदृश्य का अवलोकन किया जाए तो फर्क साफ नजर आता है, क्योंकि मनोहर सरकार की नीयत साफ है।

**निवेशकों का भरोसा बढ़ा**

प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिले, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पुराने अव्यवस्थित ढांचे को बदलने का काम

स्थान पर हैं। जी.एस.टी संग्रहण में हरियाणा का देशभर में 5वां स्थान है। इतना ही नहीं हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश निर्यात के मामले में देशभर में पांचवें नम्बर पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा व दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ कर हरियाणा देश में अग्रणी है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुताबिक प्रदेश में अभी तक 28 हजार करोड़ का निवेश हुआ है, जिसके तहत राज्य में जहां एक ओर प्रगति के नए आयाम स्थापित हुए हैं, प्रदेश की अर्थ व्यवस्था भी अपेक्षाकृत

## गांवों में मिलेंगी शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत बनाए गए दस क्लस्टरों में शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की योजना के अंतर्गत दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल, ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के मध्य जल्द ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

क्लस्टरों में डेवलपमेंट जोन के प्लानिंग एरिया को अधिसूचित कर दिया गया है। इस योजना के तहत तीन चरणों में 150 गांवों को कवर करके 10 क्लस्टर बनाए गए हैं और इनमें 751 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 376 प्रगति पर हैं। इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये मंजूर हैं, जिसमें से 548 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के दस क्लस्टरों नामतः-जिला अंबाला में मुलाना, फतेहाबाद में समैण, झज्जर में बादली, जींद में उचाना खुर्द, करनाल में बल्ला, रेवाड़ी में कोसली, पंचकूला में गणेशपुर, पानीपत में सिवाह, फरीदाबाद में तिगांव और मेवात जिला में सिंगड को तीन चरणों में विकसित करने के लिए आवंटित किया गया है।

**मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि**

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गांव को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान करना, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट, विद्यालय, स्वच्छ पानी की पूर्ति, स्ट्रीट लाइट, संपर्क मार्ग, डिजिटल साक्षरता, ई-ग्राम के अलावा सर्विसिज सेंटर स्थापित कर गांव को भी शहर जैसा बनाने की योजना है।

बैठक में बताया गया कि मिशन के तहत चयनित गांवों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास और आईटी व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक गांव को शहरों वाली सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बेहतर हुई है।

**किसानों के हित सर्वोपरि**

किसानों की खुशहाली में ही राष्ट्र और प्रदेश की खुशहाली निहित है। इसलिए किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। सरकार किसान की आय दोगुणी करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के किसानों तक उनकी मेहनत का लाभ सीधा पहुंचे, इसके लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल शुरू

## फरीदाबाद को 1525 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में आयोजित प्रगति रैली में जिला के लिए करीब 1,525 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए देकर जिला को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति सेवा, सड़क तंत्र, सामुदायिक केंद्र, विश्राम गृह, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण हेतु, ग्रेटर फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टर के विकास सहित शहरी व ग्रामीण विकास को समर्पित योजनाओं के लिए 1,480 करोड़ रुपये की नई विकासकाम परियोजनाओं की मंजूरी दी वहीं 45 करोड़ रुपये की सात योजनाओं का शुभारंभ तिगांव में किया गया।

**नलवा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की घोषणा**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार दौरे के दौरान नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। गांव मंगाली स्थित श्री बाला जी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव एवं गौ-भागवत कथा समारोह में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा द्वारा रखी गई एक दर्जन से अधिक मांगों को मंजूर किया गया।

**कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपये की 91 योजनाओं की सौगात**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 14.30 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा, थानेसर, लाडवा और शाहाबाद के लिए यहां के जन प्रतिनिधियों ने जो भी मांग रखी थी, उनमें से लगभग सभी को मंजूर कर लिया है।



एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और राज्य के किसानों द्वारा ई - खरीफ सॉफ्टवेयर में स्वयं शेड्यूलिंग करके अपनी गेहूं की फसल को मण्डियों में अपनी सुविधा के अनुसार लाना शुरू कर दिया है।



राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सहकारी क्षेत्र में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ द्वारा संचालित जींद और सिरसा के दो दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए परियोजना लागत को स्वीकृति प्रदान की है।

# कि नीयत साफ़ है

किया है। इसके तहत अब तक लगभग 5 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में 8 लाख 50 हजार किसानों को 1935 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिये गये हैं। जबकि 'भावांतर भरपाई योजना' में किसानों को लगभग 10 करोड़ रुपए की भरपाई भी की गई है।

## प्रॉपर्टी आई कार्ड से हो रहा बड़ा समाधान

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड चालू माह में वितरित किए जा रहे हैं। ऐसा करने से हरियाणा देश का पहला 'लाल डोरा मुक्त' राज्य बन जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 6302 लाल डोरा वाले गांवों में ड्रोन-फ्लाईंग तथा मैप-वन का कार्य पूरा कर लिया गया है। एट्रीब्यूट्स के बकाया कार्य के बारे में बताया गया कि राज्य के 6121 गांवों में मैप-टू का काम पूरा हो चुका है जबकि सर्वे ऑफ इंडिया के साथ 20 गांवों का शेष है। 5798 गांवों में हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 26 के तहत क्लेम व ऑब्जेक्शन को अधिसूचित किया गया है, 5643 गांवों में पूरे हो गए हैं और 155 गांवों में प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 323 गांव में अधिसूचना देना अभी शेष है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 26 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक 4919 गांवों का फाइनल मैप बना लिया गया है जबकि 750



गांवों के शेष हैं। उपायुक्तों को कहा गया है कि 750 गांवों में से जिनके क्लेम व ऑब्जेक्शन पूरे हो गए हैं उनके फाइनल मैप बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को ऑनरशिप डाटा भेज दें। बता दें सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 4919 गांवों के लिए 18 लाख 30 हजार 330 लैंड पार्सल मैप तैयार कर लिए गए हैं जबकि पूरे प्रदेश में करीब 20 लाख होने की संभावना है।

## पटवारियों को मिली मोटरसाइकिल

कोविड-19 व राजस्व से संबंधित अन्य कार्यों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर उत्कृष्ट कार्य-प्रदर्शन करने वाले पटवारियों को

सम्मानित किया गया। जीद में आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सराहनीय व अच्छे कार्य करने वाले राज्य के कुल 105 पटवारियों को सम्मानित किया। इनमें से 50 पटवारियों को एक-एक मोटरसाइकिल व प्रशंसा-पत्र जबकि शेष 55 पटवारियों को प्रशंसा-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। हरियाणा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब राज्य सरकार ने पटवारियों को उनके बेहतरीन कार्य का मान-सम्मान करते हुए उनको इनाम दिया है।

गांवों में सीवरेज व्यवस्था: गांवों में स्थित तालाबों और जोहड़ों के जीर्णोद्धार तथा संबंधित गांवों से पानी की निकासी के लिए

## पंचकूला होगा विश्व दर्शन का आदर्श महानगर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों व कार्यालयों की दृष्टि से प्रदेश की मिनी राजधानी कहे जाने वाले पंचकूला को विकसित पंचकूला बनाएंगे जो गुरुग्राम के बाद पंचकूला विश्व दर्शन का देश का दूसरा आदर्श महानगर होगा।

'जन विकास रैली' को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला शहर का हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्यम हो या सेवा क्षेत्र की परियोजनाएं हों। उन्होंने कहा कि पंचकूला शिवालिक की तलहटी में बसा गेटवे ऑफ हरियाणा है। हालांकि, गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और यह विश्व के आईकन शहरों में शामिल है। विश्व की 200 से अधिक जानी-मानी फार्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में हैं। अतः उन्होंने आश्वासन दिया कि पंचकूला को भी गुरुग्राम के बराबर विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम ताऊ देवी लाल स्टेडियम, पंचकूला में ही है। आगामी जून माह में इसी स्टेडियम में 'खेलो इंडिया' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 14 हजार से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसी प्रकार, यहां पर मोरनी में टिक्कर ताल में एअर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेलों की शुरुआत की गई है और पर्यटन की दृष्टि से पंचकूला एक उपयुक्त स्थल के रूप में उभर चुका है।

## पिंजौर की 60 एकड़ भूमि में बनेगी फिल्म सिटी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एच एम टी पिंजौर में 60 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माताओं ने यहां आने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पंचकूला में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली स्थित एमज की तर्ज पर माता मनसा मनसा देवी के पास आयुष का एमज बनाया जा रहा है। यहां निकट नेचर कैंप थापली में दिल्ली व केरल की तर्ज पर पंचकूर्मा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार, औद्योगिक दृष्टि से पंचकूला विकसित हो, इसके लिए बरवाला में एचएसआइआईडीसी द्वारा औद्योगिक संपदा विकसित की जा रही है।

600 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इस कार्य के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के करीब 3 हजार गांवों का चयन किया गया है। पंचायतों में महिलाएं: पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत

भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा ओबीसी के प्रतिनिधित्व को 8 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा राशन डिपो में 30 प्रतिशत राशन डीपो महिलाओं को आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।



## 15 खण्डों के लिए 113 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं को मंजूरी



प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के लिए गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में चिह्नित सात अल्पसंख्यक जिलों फतेहाबाद, नूंह, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, पलवल और यमुनानगर के 15 खण्डों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि की 113 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक के प्रस्ताव के मुताबिक फतेहाबाद के दो खण्डों- रतिया और जाखल में 6 परियोजनाओं पर 10.79 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में सरकारी स्कूलों में 14 टिकरिंग लैब, 11 बहुउद्देशीय हॉल और दो समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों (सीएमटीसी) का निर्माण कार्य शामिल है।

नूंह जिला के 4 खण्डों- नूंह, फिरोजपुर झिरका, नगीना और पुन्हाना में 14 परियोजनाओं पर 47.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 48 स्टाफ क्वार्टर और प्रत्येक खण्ड में चार सीएमटीसी का निर्माण कार्य शामिल है।

गुहला और सीवान दो खण्डों में पांच परियोजनाओं पर 12.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में दो मिनी ऑडिटोरियम और प्रत्येक ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों के लिए दो सीएमटीसी का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा चीका में वृद्धाश्रम भी बनाया जाएगा।

कुरुक्षेत्र जिला के पिहोवा खण्ड के लिए 5.32 करोड़ रुपए की दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें एक सीएमटीसी, एक कौशल विकास केंद्र भवन के निर्माण के साथ-साथ प्रशिक्षण केंद्र के लिए मशीनरी व उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीद शामिल है।

जिला सिरसा के चार खण्डों-बारगुधा, डबवाली, ऐलनाबाद और ओढान में 16 परियोजनाओं पर 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें सरकारी स्कूलों में 144 अतिरिक्त कक्षाओं, स्वयं सहायता समूहों के लिए चार सीएमटीसी, दो पीएचसी और एक सीएचसी का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा, सिविल अस्पताल ऐलनाबाद में 20 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु विंग के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

पलवल के हथौन खण्ड में पांच परियोजनाओं पर 4.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सीएमटीसी का निर्माण, 30 सरकारी स्कूलों की चारदीवारी, 12 सरकारी स्कूलों में वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम का कार्य शामिल है। इसके अलावा, बैठक में सरकारी स्कूलों में शौचालय (छह लड़कियों के लिए और तीन लड़कों के) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

यमुनानगर जिले के छछरौली खण्ड के लिए चार करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें सीएचसी, खिजराबाद में डॉक्टरों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण, मल्टी स्पेशलिटी हॉल, 11 आंगनवाड़ी केंद्र, ऑडिटोरियम भवन और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए सीएमटीसी का निर्माण करना शामिल है।



खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के लिए सरकार अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में दूध तथा अन्य खाद्य उत्पादों के लिए जांच सुविधाएं स्थापित करेगी।



हैफेड ने वर्ष 2021-22 में 23 सफलतापूर्वक निर्यात शुरू कर दिया है और पांच करोड़ रुपए के पांच निर्यात ऑर्डर निष्पादित किए हैं।

# आधुनिक खेती बना स्टार्ट-अप

संगीता शर्मा

युवा को जब तक सरकारी नौकरी व अच्छी सैलरी की प्राइवेट नौकरी न मिले तो उन्हें अपने पुरतैनी खेती को रोजगार के रूप में स्वीकारने से

हिचकिचाना नहीं चाहिए। खेती अब घाटा का सौदा नहीं है। पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक खेती को अपनाएं। तब वह आराम से अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।

इसका साक्षात प्रमाण रेवाड़ी के निमोठ गांव के प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार है।

उन्होंने बताया कि वे गत पांच साल से आधुनिक खेती कर रहे हैं। इस खेती ने उनके जीवन में ख़ासा बदलाव लाया है। दो एकड़ जमीन में गोभी के बीज सिंचाई प्रणाली से उगाने के लिए परामर्श दिया। लेकिन उनके पास सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए रुपए नहीं थे। तब जंग बहादुर ने उन्हें एडवांस में

35,000 रुपए देकर सिंचाई प्रणाली लगवाई व गोभी के बीज तैयार किए। इससे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से 1.80 लाख रुपए लाभ हुआ। कृष्ण ने बताया कि उसके बाद खेती को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक ही खेत में गोभी की फसल के बाद तरबूज व बैल वाली अन्य फसलें उगाईं। इससे उनकी आमदनी दोगुनी होनी शुरू हो गई। बागवानी में उन्होंने अधिक से

अधिक लाभ कमाना शुरू कर दिया।

कृष्ण ने बताया कि वह 'धवना किसान उत्पादक संगठन' के सदस्य है और किसान क्लब से भी जुड़े हुए हैं। इस संगठन के माध्यम से नई जानकारी, प्रशिक्षण और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। उनका कहना है कि बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा किसानों को मल्लिचंग, सिंचाई प्रणाली, फलों की खेती व अन्य खेती के लिए बहुत रियायतें दी जाती हैं, जिससे कारण किसान बागवानी की तरफ अधिक रुख कर रहे हैं। वह बताते हैं कि पैदावार को रेवाड़ी की मंडी, स्थानीय विक्रेताओं व खेतों से ग्राहक खरीदकर ले जाते हैं और उन्हें सब्जियों व फलों को बेचने के लिए ईंधर-उधर भटकना नहीं पड़ता।

## गुणकारी सतावर

उन्होंने बताया कि डेढ़ एकड़ जमीन में जैविक खेती कर रहे हैं इसमें आधा एकड़ में सतावर की खेती व एक एकड़ नेट हाउस में नींबू व टमाटर की खेती कर रहे हैं। यह खेती स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभप्रद है। सतावर एक गुणकारी औषधि, इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है एक तो पाउडर बनाकर दूध के साथ सेवन किया जाता है और दूसरा हम अपनी दूध देने वाली गाय या भैंस को खिला दें जिससे दूध में सतावर का असर आ जाता है। वह पिछले तीन सालों से सतावर की खेती कर रहा है और गौली सतावर की कीमत घर पर 80 रुपए प्रति किलो और होम डिलीवरी पर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं।

# राज्यपाल ने क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केन्द्र का दौरा किया



राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार बागवानी व सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। मशरूम उत्पादन भी स्वरोजगार का अवसर है। मशरूम की मांग के हिसाब से उत्पादन बहुत कम है। मशरूम के अन्य उत्पाद बनाकर भी आय को बढ़ाया जा सकता है।

श्री दत्तात्रेय ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केन्द्र, मुखल का दौरा किया। उन्होंने स्पोन लैब (मशरूम बीज लैब) का निरीक्षण किया और मशरूम का बीज कैसे तैयार किया जाता है, इस बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने रि-ट्रैकटेबल पोलि हाउस में

किसानों को दिखाने के लिए लगाई गई रंग बिरंगी शिमला मिर्च को भी देखा। उन्होंने कहा कि आज मशरूम ही नहीं, बल्कि मशरूम से बने उत्पाद भी बाजार में आ रहे हैं और ग्राहक इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए मशरूम के उत्पादन के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि गेहूं और धान की फसलों की बजाय किसानों को अपनी आय को दोगुना करने के लिए फल, फूल व सब्जियों की खेती पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

# सरकारी योजनाओं से आसान हुई खेती

भिवानी का छोटा सा गांव झुपा कलां। कभी से गांव में पानी का बड़ा संकट था लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार के प्रयास से बदलाव आया है। किसानों में खुशहाली आई है। नहरी पानी व खेतों में लगे सोलर पंप से अब यह गांव गुलजार हो रहा है। काफी किसानों ने कपास, गेहूं व सरसों व बागवानी की खेती शुरू की है। किसानों ने गेहूं, सरसों का रकबा भी बढ़ाया है। अब यहां के किसान एक ही बार में कई-कई फसलें लेकर मालामाल हो रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है की यहां की मिटटी बालु है जिसमें सभी फसलों के उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं।

जितेंद्र गोदारा 100 एकड़ के जमींदार हैं। वे पहले बाजरा व चने की खेती करते थे लेकिन अब गेहूं व सरसों का रकबा भी बढ़ाया है। इस बार 32 एकड़ में सरसों, 16 एकड़ में गेहूं व 3 एकड़ में मैथी की खेती के अलावा 12 एकड़ में अमरूद व 10 एकड़



में किन्नु की खेती की है। वे बागवानी सुक्ष्म सिंचाई के आधार पर करते हैं जबकी दूसरी खेती ड्रिप विधि से होती है।

सरकार से उन्होंने सोलर पंप, गोबर गैस प्लांट, पानी के तालाब पर, पाईपों पर जो सब्सीडी दी उसकी बदैलत काफी लाभ हुआ। ड्रिप पर 80 प्रतिशत सब्सीडी मिली जिसमें उनका प्रति एकड़

40 से 45 हजार प्रति एकड़ खर्च आया।

उन्होंने खेत में गोबर गैस प्लांट लगाया है जिसमें उन्हें 50 प्रतिशत सब्सीडी मिली। खाद पर भी सरकार किसानों सब्सीडी दे रही है। सोलर पर 75 प्रतिशत सब्सीडी मिली है। जितेंद्र ने बताया सरकार से मिलने वाली सब्सीडी से खेती आसान हो रही है। अन्य किसान भी इनका लाभ उठाकर खेती की दिशा व दशा बदल सकते हैं।

# गन्ने की रोपाई का समय

प्रदेश में गन्ने की फसल को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। यहां सवा लाख हेक्टेयर में करीब 75 हजार किसान ऐसे हैं जो गन्ने की बिजाई को प्राथमिकता देते हैं। गन्ने की इस फसल की किसान तीन बार बिजाई करते हैं। अप्रैल का महीना प्रारंभ होते ही किसान इसकी रोपाई का कार्य प्रारंभ कर देते हैं।

इस फसल पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से यह एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। गहरी दोमट मिट्टी के अलावा रेतीली मिट्टी में इसकी पैदावार अधिक मात्रा होती है। मुख्यतया उसके उत्पादन के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जल भराव से फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। गन्ने के पौधों शुष्क और आद्र जलवायु में ज्यादा पैदावार देते हैं। यह फसल वर्ष भर में पैदावार देना आरम्भ कर देती है।

सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए जुताई के बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पुरानी गोबर की खाद का प्रयोग कर रोटोवेटर से जुताई करनी चाहिये। जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती।

गन्ने की फसल का उचित प्रबंधन एवं देखभाल खरपतवार नियंत्रण का आवश्यक है। गर्मियों के मौसम में सप्ताह में एक बार

पौधों को पानी देना होता है। बारिश के मौसम में पौधों की रोपाई जरूरत पड़ने पर ही की जाती है। दवाई की पूरी मात्रा सिफारिश किये गये समय पर ही प्रयोग करना उचित है। किसानों को स्प्रे तब करना चाहिये जब मौसम साफ हो और हवा की गति ना हो। गन्ने के खेत में खरपतवार पर नियंत्रण के लिए किसान प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गन्ने की उन्नत किस्मों में सीओ 160, सीओ 238, सीओ 239 सीओजे 85 सी ओ 15023, सीओ 118, सीओ 11 सीओ 5011, सीओ 8 272 प्रमुख हैं। इसके अलावा कई नई-नई वैरायटी जैसे की सीओ 15023 भी मौजूद हैं। अच्छे व निरोगी बीज का प्रयोग करना चाहिये इससे अधिक पैदावार होती है। एक एकड़ में 15 से 20 क्विंटल बीज आसानी से लग जाता है व करीब 250 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। अच्छी देख-रेख कर किसान 650 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन कर सकते हैं।

कृषि विकास अधिकारी अनिल गुलिया कहते हैं बीज उपचार बेहतर होना चाहिए। अच्छी फसल लेने के लिए गन्ने की पौरी को उचित मात्रा के घोल में डुबाकर रखना होता है। इससे डंडियों के अंकुरण के समय उन्हें रोग लगने का खतरा कम हो जाता है।

—सुरेंद्र सिंह मलिक



बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिले का शेड्यूल जारी हुआ है। अधिनियम के तहत ऐसे स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।



खरखौदा के गांव रिद्धाऊ के तरुण गहलावत ने गूगल में बतौर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद पर नियुक्ति पाई है। उसे सवा करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे, जबकि 18 वर्ष का होने पर यह पैकेज करीब दो करोड़ रुपए का होगा।

# मेहनती व ईमानदार पुलिस कर्मी होंगे सम्मानित

## मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला



पुलिस विभाग में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन राज्य पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें वीरता के लिए मुख्यमंत्री-पदक, जांच में उत्कृष्टता के लिए गृहमंत्री-पदक और अन्य बेहतर कार्य करने के लिए हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा-पदक दिया जाएगा।

पहला पदक हरियाणा पुलिस के उन सभी रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, जो जीवन और संपत्ति को

बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने, कट्टर अपराधियों का सामना करने, जन आंदोलन पर नियंत्रण करने, बड़े पैमाने पर कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने व प्रबंधन करने अथवा रिस्क का पहलू से ही अनुमान लगाने, सामान्य कर्तव्य से ऊपर और विशेष बहादुरी के असाधारण और विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

दूसरा पदक उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो जांच के नवीन, वैज्ञानिक तरीकों, फोरेंसिक व ऑनलाइन जांच

उपकरणों का उपयोग करते हैं, चार्जशीट की त्वरित फाइलिंग करके दोषी का दोष सिद्ध करने में खास भूमिका अदा करते हैं। इससे राज्य में अपराध की जांच के उच्च मानकों को बनाए रखने तथा पुलिस बल के बीच व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यही नहीं, दोषियों को सजा दिलाने की दर में वृद्धि होगी जिससे समाज को लाभ पहुंचेगा।

तीसरा यानी हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक पुलिस के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो कानून और

व्यवस्था, आईटी तकनीक, यातायात प्रबंधन, पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक कार्य, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस विभाग की अन्य सभी नौकरियों या रिकॉर्ड-कीपिंग और हाउसकीपिंग के माध्यम से बेहतर प्रशासनिक कार्य में सहायता करेंगे। इसके लिए वे पुलिसकर्मी भी पात्र होंगे जो न केवल नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करते हैं, बल्कि जो किसी औपचारिक पुरस्कार या इनाम के लिए अभी तक मान्य नहीं हुए थे।

इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वही पर बाई

जेब के ऊपर रंगीन डिस्ले के साथ एक पदक, स्कॉल, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र के साथ 21 हजार रूपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप बी और सी पुलिस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवा में छह महीने का विस्तार (यदि वे सेवा में किसी अन्य विस्तार का लाभ नहीं उठा रहे हैं) दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में पदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में दस से अधिक नहीं होगी।

—संवाद ब्यूरो

## पूजा को मिला 'नारी शक्ति पुरस्कार'

### बुलंद इरादों से शुरू किया स्टार्ट-अप

संगीता शर्मा

गुरुग्राम के छोटे से गांव चंदू की महिला उद्यमी व किसान पूजा शर्मा ने अपनी मेहनत के बूते हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह और कृषि विज्ञान केंद्र, गुरुग्राम से जुड़कर बेकरी के कारोबार को काफ़ी बढ़ा लिया है। पूजा अब 12-15 लाख प्रति वर्ष कमा रही है। उनके इस काम की सराहना करते हुए हाल ही में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया है। वे कहती हैं कि महिला उद्यमियों के साथ यदि प्रगतिशील किसान भी शामिल हो जाएं तो इससे किसानों की आय दोगुनी नहीं तिगुनी हो सकती है।

पूजा शर्मा झज्जर के बाकरा गांव में पली-बढ़ी और दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की। वे बताती हैं कि घर पर कार्यालय बनाकर सोयाबीन नट्स, बाजरे की खिचड़ी, बिस्कुट, लड्डू, आलू चिप्स, कुकीज आदि जैसे विभिन्न उत्पाद तैयार किए। वर्ष 2017 में, उन्होंने एक बेकरी इकाई शुरू की और वर्तमान में, वे राज्य के साथ-साथ देशभर में 11 से अधिक उत्पाद बेचते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली व मुंबई की एनजीओ और नामी कंपनियां अपनी मांग के अनुसार उत्पाद भी तैयार करवाती हैं। स्वयं माल उपलब्ध करवाती हैं और उनसे तैयार उत्पाद पर अपने ब्रांड स्लिप लगाकर मॉल्स व होटल्स में बेचती हैं। हैफेड के स्टोर में भी उनके समूह द्वारा तैयार



और नए लोग भी जुड़ते गए। इसके अतिरिक्त इन दिनों वह सरकार की एक्सप्रेस योजना के तहत कार सीखने का प्रशिक्षण ले रही है, जिसके तहत कार खरीदकर अपने उत्पाद की बिक्री करने व एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में आसानी होगी।

ऋण से हुई आत्मनिर्भर

पूजा ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, केवीके और एनजीओ के सहयोग से अपने उत्पाद तैयार करने की मशीनें व अन्य फर्नीचर खरीदी और इससे कारोबार बढ़ता चला गया। उन्होंने बताया कि

किए उत्पाद बिकते हैं।

उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही खेतों व पशुओं का काम करती थी, जिससे उसको पशुपालन में आसानी हुई। वह बताती हैं कि अब काम बढ़ने से पशुपालन का काम बंद कर दिया है। 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र, गुरुग्राम से सिलाई का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद केवीके से रोस्टिड सोयाबीन, बाजरे के बिस्कुट, खिचड़ी, लड्डू, गेहूं का दलिया व अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसकी मार्केटिंग के लिए कृषि मेले, ट्रेड फेयर, सूरजकुंड मेले व अन्य मेले में जाना शुरू किया। वहां उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई



'क्षितिज'

स्वयं सहायता समूह के अलावा आठ स्वयं सहायता समूह तैयार किए हैं। जल्द ही दो समूह तैयार होने वाले हैं। पीवी ग्राम संगठन से भी जुड़ी हुई है। पूजा ने बताया कि सरकार की योजनाओं से समूह विशेष लाभ उठाता है और ऋण की सुविधा भी मिलती है। पूजा ने बताया कि समूह की सदस्य बीपीएल परिवार व दिहाड़ीदार मजदूर हैं और प्रतिदिन 250 से 300 रूपए मेहताना कमाती हैं।

## साहित्य अकादमी द्वारा वार्षिक सम्मानों की घोषणा



हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना वर्ष 2021 के लिए विभिन्न सम्मानों हेतु साहित्यकारों का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि डॉ. जयगवान गोयल, कुरुक्षेत्र को आजीवन साहित्य साधना के लिए अकादमी द्वारा 'विशेष साहित्य साधना सम्मान' व समग्र लेखन के लिए 'आजीवन साहित्य साधना सम्मान' के लिए वरिष्ठ साहित्यकार रोहित यादव, मंडी अटेली का चयन किया है। 'महाकवि सूरदास सम्मान' वरिष्ठ साहित्यकार एवं गजलकार हरे राम समीप, फरीदाबाद को दिया जायेगा। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए वरिष्ठ गीतकार एवं चिंतक डॉ. रमाकांत शर्मा, भिवानी का चयन किया गया है।

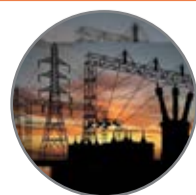
हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए डॉ. प्रद्युम्न भल्ला, कैथल को 'बाबू बालमुकुंद गुप्त सम्मान' तथा साहित्यिक पत्रकारिता के लिए दिये जाने वाले 'लाला देशबन्धु गुप्त सम्मान' के लिए वरिष्ठ कवि एवं सम्पादक रघुविन्द्र यादव, नारनौल का चयन किया गया है। हरियाणवी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के

लिए वी.एम. बेचैन, भिवानी का 'पंडित लखमीचंद सम्मान', हरियाणवी भाषा एवं साहित्य के लिए दिए जाने वाला 'जनकवि मेहर सिंह सम्मान' लहना सिंह अत्री, करनाल को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने के लिए दिए जाने वाले 'हरियाणा गौरव सम्मान' के लिए सुप्रसिद्ध गीतकार एवं चिंतक डॉ. राजेन्द्र गौतम, दिल्ली का चयन किया गया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाले 'श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान' के लिए अंजु दुआ जैमिनी एवं नमिता राकेश, फरीदाबाद का चयन किया गया है। 'कवि दयाचंद मायना सम्मान' शमशेर कौसलिया, महेन्द्रगढ़ को प्रदान किया जाएगा।

अकादमी द्वारा वर्ष 2021 से 'विशेष हिंदी सेवा सम्मान' आरंभ किया गया है। इस सम्मान के लिए वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं चिंतक डॉ. शिवकुमार खंडेलवाल, सोनीपत, रवि शर्मा, लंदन (रोहतक), डॉ. सुरेन्द्र गुप्त, अम्बाला, आशा खत्री लता, रोहतक, राजेश चेतन, दिल्ली और महेन्द्र जैन, हिसार का चयन किया गया है। युवा लेखक सम्मान के अंतर्गत 'स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान' के लिए श्रुति राविश, सोनीपत का चयन किया गया है।



'हरियाणा-इथियोपिया निवेश आयोग (ईआईसी)' की दो दिवसीय बैठक गुरुग्राम और चंडीगढ़ में आयोजित की गई। हरियाणा राज्य और इथियोपिया के बीच सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए।



बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि गर्मी के मौसम में हिसार सर्कल के उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति देने के लिए 13 बिजली घरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

# ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर



अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 वें प्रकाश पर्व समारोह के उपलक्ष्य में इस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को सम्मान देने के लिए 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 अप्रैल, 2022 को पानीपत में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए एक भक्ति गीत का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा डिजाइन किए गए हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं वाले पोस्टर भी लॉन्च किए।

मार्च 2021 से, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उत्सव के उपलक्ष्य में देश में विभिन्न धार्मिक

और सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुके हैं। हालांकि, कोरोना महामारी के कारण हरियाणा में अधिकांश कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन अब राज्य सरकार ने 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में इवेंट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी सिख श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध रागी और कथा वाचकों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं न केवल हमारे लिए एक दुर्लभ विरासत हैं बल्कि एक मजबूत और नैतिक रूप से प्रबुद्ध समाज के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नींवों में से एक हैं। समारोह का उद्देश्य श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा प्रचारित सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के संदेश का प्रचार करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा न केवल श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ बल्कि सभी दस सिख गुरुओं के साथ एक विशेष बंधन



साझा करता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने अपने जीवनकाल के दौरान राज्य के लगभग हर कोने में यात्रा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को दुनिया के सबसे महान मानवतावादी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से समर्पण और बलिदान की भावना सीखने की जरूरत है। आज हमारा परम कर्तव्य बनता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी और अन्य धर्म गुरुओं और संतों की

शिक्षाओं, विचारधाराओं और दर्शन को समाज में, विशेषकर युवाओं में प्रचारित प्राप्त करें। सीएम ने जनता से आग्रह किया कि वे हरियाणा के हर कोने से इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंच कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था जो करनाल से शुरू होकर यमुनानगर में संपन्न हुआ था। वर्ष 2019 में सिरसा में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व का भी आयोजन किया गया था। राज्य सरकार समय-समय पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं, राज्य स्तरीय समारोहों, सेमिनारों का आयोजन करके धर्म गुरुओं, संतों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है।

**गुरु जी से मिलने जब कश्मीरी पंडित पहुंचे**

श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान के कारण ही पूरी मानवता ने उन्हें 'हिंद दी चादर' की उपाधि से नवाजा है। श्री

गुरु जी ने न केवल हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण से बचाया, बल्कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की भी बहुत मदद की, जो औरंगजेब के दबाव में जीवन जी रहे थे।

इतिहास बताता है कि जब कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी व्यथा बताने श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलने गया, तब गुरु जी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म बच सकता है। यह सुन कर 9 वर्ष के बालक गोबिंद राय (गुरु गोबिंद सिंह जी) ने कहा कि 'पिता जी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। आप अपना ही बलिदान क्यों नहीं देते।' अपने पुत्र की बात सुन कर गुरु जी ने पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि, 'यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब स्वतः ही इस्लाम स्वीकार कर लेंगे।' औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को तब बंदी बना लिया गया था, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना शीश धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया।

## गुरु तेग बहादुर जी की चरण रज से धन्य धमतान साहिब

डॉ. चंद्र त्रिखा

वर्ष 1665 में हरियाणा में अधिकांश क्षेत्रों के लिए 'बांगर देश' शब्द का प्रयोग होता था। उसी बांगर प्रदेश में अप्रैल माह के आसपास पहली बार गुरु तेग बहादुर जी का आगमन हुआ। वहां गुरुजी अपने एक श्रद्धालु और अपने क्षेत्र के बेहद सम्मानित 'मसंद' भाई दगो के आवास पर ठहरे। उन्हीं के आवास पर सवेरे शाम गुरुजी का प्रवचन होता।

कुछ दिन बाद गुरुजी ने वहां से कीरतपुर जाने का निर्णय लिया। लेकिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनसे अरदास की कि गुरुजी उसी स्थल अर्थात् धमतान को अपना दूसरा मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएं। गुरुजी ने सभी श्रद्धालुओं को हर संभव समझाने का प्रयास किया कि अब तक बकाला व कीरतपुर ही सिक्ख परंपरा के मुख्य प्रचार केंद्र रहे हैं और उनके लिए वहां के श्रद्धालुओं को निराश करना संभव नहीं होगा। लेकिन जब धमतान

साहब के श्रद्धालु भी भावुक हो उठे तो गुरुजी ने सहमति दे दी। अगले ही दिन यानी मई 1665 के प्रथम सप्ताह में एक कुएं की खुदाई और गुरु-घर के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया।

गुरुजी पास के जंगल में घूमने निकले तो उन्हें 'बांगर' के पुलिस-प्रमुख द्वारा बंदी बना लिया गया। क्योंकि शाही फरमान के अनुसार वहां गैर मुस्लिम को हथियार लेकर जंगल में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। गुरुजी और उनके अन्य बंदियों में भाई मती दास, भाई सती दास, भाई गुआल दास, गुरदास बड़तिया, संगत जेटा, भाई दगो, भाई दयाल दास को लाल किले में औरंगजेब के सामने पेश किया गया।

औरंगजेब ने पेशकश की कि

यदि वे शस्त्र रखना चाहते हैं तो उन्हें इस्लाम कुबूल करना होगा। मगर गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी सूरत अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। इस पर क्षुब्ध औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदण्ड देने का आदेश दिया।

उस समय राजा जय सिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह भी दरबार में मौजूद थे। उसने शहशाह से आग्रह किया कि इतना कड़ा दण्ड न दिया जाए। कुछ पल सोचने के बाद औरंगजेब ने उन सबको कुंवर राम सिंह की हिरासत में ही रखने का आदेश दिया। लगभग दो माह तक कुंवर राम सिंह ने उन सबको अपने आवास पर रखा और फिर रिहा कर दिया।

गुरुजी वहां से बंगाल, बिहार, असम और उत्तरप्रदेश के कुछ नगरों की धर्म प्रचार-यात्रा करते

हुए 1667 की गर्मियों में अपने बेटे धर्मपत्नी व अन्य परिजनों से मिले। चौमासा काटने के बाद वे मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, कांतानगर, मालदा व ढाका गए।

गुरुजी ने मार्च 1670 में वापसी यात्रा आरंभ की। दिल्ली से गुरुजी तरावड़ी, कुरुक्षेत्र, पिहोवा और धमतान होते हुए सैफाबाद पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरने के बाद गुरुजी मुलौवाल, करतारपुर, सुलतानपुर होते हुए बकाला पहुंचे। लगभग डेढ़ वर्ष वहां बिताने के बाद वह चक नानकी गए। वहीं पर 25 मई, 1675 को कश्मीरी ब्राह्मणों का शिष्टमंडल उनकी सेवा में उपस्थित हुआ।

सोनीपत का छोटा सा कस्बा बड़खालसा सिख-इतिहास में विशेष महत्व रखता है। कस्बे के निवासियों को इस बात का गर्व है कि उनके एक पूर्वज भाई कुशल सिंह (भाई कुशल सिंह) ने नवम् गुरु की सेवा में अनूठा बलिदान दिया था।

जिस दिन चांदनी चौक में

तत्कालीन आततायी औरंगजेब के आदेश से नवम् गुरु को शहीद किया गया, उसी शाम भीषण काली आंधी ने दिल्ली के अनेक क्षेत्रों को अपनी लपेट में ले लिया था। आततायी का यह भी हुक्म था कि कोई भी व्यक्ति गुरुजी के शरीर का कोई अंग वहां से न हटाए। उस माहौल में गुरुजी के एक श्रद्धालु भाई जैता ने लपक कर उनका कटा हुआ सिर उठाया और गहन अंधेरे में गायब हो गया। लगभग उसी समय लम्बीशाह वन्जारा नामक एक अन्य श्रद्धालु ने घटनास्थल पर पहुंचकर गुरु जी का शेष शरीर वहां से उठाया, उसे अपने कपास लादने वाले छकड़े में रूई की गांठों के तले छिपाया और वहां से अपने रायसीना गांव के आवास की ओर चल पड़ा।

